details regarding actual allotment of FPS/ kerosene oil depots granted to SC/STs are not maintained by the Central Government.

हिमाचल प्रदेश में उचित दर दुकानें

3811. श्री महेश्वर सिंह : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले की रोहड़ू और चिड़गांव तहसीलों की जनता को उचित दर पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपूर्ति निगम की उचित दर दुकानें खोलने का विचार रखती है;

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अभी तक उपर्युक्त तहसीलों में उचित दर दुकानें न खोले जाने के क्या कारण हैं जबकि राज्य के दूसरे सभी हिस्सों में लोगों की सुविधा के लिए ऐसी दुकानें खोली गई हैं; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में और अधिक ऐसी दुकानें खोलने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक और इन दुकानों को किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Participation by women and rural people in consumer movement

3812. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the participation of women and rural people in the consumer movement is at present quite negligible;

(b) if so, what are the detail* of thiir participation, State-wise; and

(c) what steps Government have taken or propose to take to involve their maximum participation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) For strengthening and broadbasing the consumer movement in the country, the Government encourages the participation of all consumers including women and rural people. Government has taken a number of steps including provision of financial assistances to voluntary consumer associations, organising national/regional/state level seminars for involvement of people at the grass-root level and institution of national awards under which preference is given to women and those working in rural/tribal areas. Government have also announced a separate National Award for women consumer activists from this year. Apart from the above, special provisions have been made in the Consumer Protection Act, 1986 and the Rules made thereunder for nomination of farmers and women in the Central Consumer Protection Council and State Consumer Protection Councils. The three-tier consumer disputes redressal agencies also have one woman member each as provided under the statute.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति

3813. श्री अजीत जोगी :

श्री छोटू भाई पटेल :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन घटिया